Dr. Pankaj Kumar Yadav
S.N.S R.K. College Saharsa
Depart L.S.W

Page No.
Date

23/04/2020

4 Q. Define Social planning: Meaning, Objectives, Scope, and forms of Social planning in India : भारत में सामाजिक योजना को बढ़ावा, और अर्थ, विकल्प, एवं क्षेत्र को परिभाषित कीजीए।

Ans – भारत में योजना की प्रक्रिया प्रथम पंचवर्षीय योजना के 1 अप्रैल, 1951 को प्रारम्भ हुई, परन्तु आर्थिक विकास के साधन के रूप में योजना का सैद्धान्तिक प्रयास स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ही किया जाने लगा था। सर एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में अपने ग्रंथ 'दि प्लांड इकॉनोमी आफ इण्डिया' में देश आर्थिक विकास की एक दस वर्षीय योजना प्रस्तुत की, जिससे देश के राष्ट्रीय आय को दसवें वर्ष में देश की आर्थिक विकास दुगुना किया जा सके। विश्वेश्वरैया ने अपनी योजना में कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त श्रम शक्ति को उद्योग में लगाने पर बल दिया था।

भारत के लिए योजना बनाने का पहला प्रयास 1938 में किया गया, जबकि कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाषचन्द्र बोस ने पं. जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति (National Planning Committee - NPC) की स्थापना की। इस समिति ने योजना के विभिन्न पहलू पर विचार कर कई रिपोर्ट प्रकाशित की, जो परवर्ती योजना का आधार बनी। राष्ट्रीय योजना समिति ने यह मत व्यक्त किया कि समस्त मूल उद्योगों और सेवाओं, खनीज संसाधनों, रेलों, जल मार्गों, नौ-परिवहन और अन्य सार्वजनिक उपयोगिता वाले उद्योगों पर राज्य का स्वामित्व या नियंत्रण होना चाहिए तथा यह सिद्धान्त उन बड़े पैमाने के उद्योगों पर भी लागू होना चाहिए जिनमें एकाधिकार कायम होने की संभावना है। समिति की धारणा थी कि आर्थिक विकास के लिए अर्थव्यवस्था का औद्योगिकरण आवश्यक है, किन्तु औद्योगिकरण का अर्थ यह की कुटीर उद्योग की उपेक्षा की जाय। विभिन्न अर्थशास्त्रीयों की एक समिति ने 1941 में रामास्वामी मुदालियर के नेतृत्व में परिवहन, बैंकिंग, उद्योग, वाणिज्य, मुद्रा, एवं विदेशी मुद्रा से संबंधित सैद्धान्तिक नीतियों के निर्धारण हेतू सुझाव प्रस्तुत किए। जनवरी 1944 में मुंबई के आठ उद्योगपतियों ने देश के आर्थिक विकास हेतू एक योजना 'ए प्लान आफ इकॉनोमिक डेवलपमेंट (A Plan of Economic Development

नाम से प्रकाशित की, जो बम्बई योजना (Bombai Plan) के नाम से प्रसिद्ध है। भारती श्रम संघ की ओर से विश्व प्रसिद्ध क्रान्तिकारी एस. एन. राय ने अप्रैल 1945 में एक विस्तृत वृहत दस वर्षीय जनता योजना (Peoples Plan) प्रतिपादित किया गया। जहाँ बम्बई योजना में कृषि की तुलना में उद्योगों को अधिक प्रथमिकता दी गई थी, वहीं रूसी योजना के अनुभव प्रेरित जनता योजना में सामुहिक या सरकारी खेती पर बल दिया गया और इसके लिए भूमि का राष्ट्रीयकरण सिफारिश की गई। जनता योजना में लोगों के जीवन स्तर को शिघ्र उन्नत करने के लिए उपभोग-वस्तु उद्योग के विकास पर बल दिया गया था। इसके अतिरिक्त 1944 में ही महात्मा गाँधी के आचार्य श्रीमन्नारायण ने गाँधीवादी योजना रखा था। इस योजना में कृषि और उद्योग एक साथ-साथ संतुलित विकास पर बल दिया गया तथा कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। इन सभी योजनाओं का सिर्फ ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि ये सभी कागजी योजनाएं थी जिन्हें वास्तविक रूप से क्रियान्वित नही किया गया था। अगर हम एक निम्न तालिका पर दृष्टिपात करें तो योजना का लक्ष्य एवं व्यय परिलक्षित होता है।

योजना का स्रोत

तालिका स्वतंत्रता पूर्व प्रस्तावित योजनाओं के लक्ष्य एवं व्यय की राशि

लक्ष्य	एम.वी.	बंबई योजना (करोड़ रु.)	जनता योजना	गाँधी वादी योजना
	जीवन स्तर को दो गुणा करना	राष्ट्रीय आय को तीन गुणा करना	जीवन स्तर को चार गुणा करना	प्रति व्यक्ति की आय को चार गुणा करना
समयावधि	10 वर्ष	15 वर्ष	10 वर्ष	10 वर्ष
सिंचाई व शक्ति	—	1240	2950	1,175
परिवहन व संचार	—	940	1,500	400
सामाजिक सेवाएं	—	3,140	4,950	555
उद्योग	—	4,480	5,600	1,350
अन्य	—	200	—	20
कुल योग		10,000	15,000	3,500

जैसा कि हमें यह ज्ञात हो चुका है योजना अर्थ

Dr Pankaj Kumar

Ajanta
Page No.
Date

बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए जीविकोपार्जन का उपाय ढूंढना ही योजना कहलता है। भारत अंग्रेजों का गुलाम देश रहा है यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर आश्रित रही है। अंग्रेजों के लूट-घसोट से इस देश की अर्थव्यवस्था काफी कमजोर कर दी गई। इस बातों को ध्यान में रखते हुए योजना का गठन किया गया।

भारत में योजना आयोग का गठन परामर्शदात्री एवं विशेषज्ञ संस्था के रूप में योजना आयोग का गठन मार्च 1950 में किया गया। इसका पदेन अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होंगे हैं। योजना आयोग ने देश के आर्थिक विकास के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) अप्रैल 1951 में आरम्भ की।

भारत में योजना आयोग का मुख्य निम्नलिखित कार्य हैं। (i) देश की भौतिक, पूंजीगत मानवीय संसाधनों का अनुमान लगाना तथा उसमें वृद्धि संबंधि उपाय सुझाना।

(ii) राष्ट्रीय संसाधनों के अधिक-से अधिक प्रभावी एवं संतुलित उपयोग हेतु योजना की रूपरेखा तैयार करना।

(iii) योजना के विभिन्न चरणों का निर्धारण करना एवं प्राथमिकता के आधार पर संसाधनों का आवंटन करने का प्रस्ताव देना।

(iv) योजना के प्रत्येक भाग की कार्यशीलता के आधार पर का आकलन करना और सुधारात्मक सुझाव देना।

(v) आर्थिक विकास में बाधक तत्वों की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करना तथा वर्तमान समय में सामाजिक एवं राजनैतिक परिस्थितियों में आर्थिक-सामाजिक उन्नति हेतु आवश्यक शर्तों को निर्धारित करना।

भारत में बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप रोजगार नहीं मिलने के कारण यहाँ के 27.1 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। एक आँकड़े के अनुसार गरीबी रेखा का मापदण्ड निम्न प्रकार है।

भारत में निर्धनता रेखा का आकलन दैनिक कैलोरी उर्जा से है। जैसा कि यदि कोई व्यक्ति को ग्रामीण क्षेत्र के 2400 कैलोरी उर्जा प्रति दिन की सीमा से कम तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी उर्जा प्रति दिन की सीमा से कम उपभोग करता है तो

या ग्रामीण क्षेत्र के प्रति व्यक्ति की आय 22400 रुपया प्रतिवर्ष
तथा शहरी क्षेत्र के प्रति व्यक्ति की आय 25600 रुपया प्रतिवर्ष कम
है तो उसे गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है

लकड़वाड़ा फार्मूले ~~में देश एवं अलग-अलग~~ के आधार पर योजना आयोग द्वारा घोषित आँकड़े के अनुसार देश के 32 में से 18 राज्यों एवं केन्द्र शासित संघ राज्यों में गरीबी अनुपात देश औसत स्तर से अधिक अनुमानित किया गया है।

गरीबी अनुपात में उड़ीसा राज्य का स्थान सबसे ऊँचा है जहाँ लगभग 47.2% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है बिहार 42.6%, तथा मध्य प्रदेश 37.43% का क्रमशः दूसरा तथा तीसरा स्थान है।

भारत में सरकार के द्वारा आर्थिक विकास के लिए एवं प्रति व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए ही रोजमूलक योजना चलायी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद योजना बद्ध रोज मूलक कुछ विशेष कार्यक्रम निम्न प्रकार से दर्शाए जा सकते हैं: —

(i) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, (ii) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (iii) जवाहर योजन, (iv) सुनिश्चित रोजगार योजना, (v) दस लाख कूप योजना, (vi) इन्दिरा आवास योजना, (vii) प्रधानमंत्री रोजगार योजना (viii) ग्रामीण युवक स्व-रोजगार प्रशिक्षण योजना, (ix) समेकित ग्रामीण विकास कार्य-कम, (x) सुखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, (xi) मरुस्थल विकास कार्यक्रम, (xii) ग्रामीण क्षेत्र महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, (xiii) ग्रामीण कारीगर योजना, (xiv) गंगा कल्याण योजना (xv) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, (xvi) पंचायती राज्य का सुदृढ़ीकरण (xvii) भूमि सुधार कार्यक्रम (xviii) निर्धनों के लिए नगरीय आधार-भूत सेवा योजना, (xix) स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, (xx) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, (xxi) संसद निधि विकास योजना, (xxii) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, (xxiii) वाल्मिकी आवास योजना (xxiv) प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना, (xxv) काम के बदले अनाज कार्यक्रम;

उपरोक्त योजनाए से अलग स्वरोजगार पैदा करी

करने वाली स्वर्णजयंती रोजगार योजना पर दृष्टिपात करें।

स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना दो भागों में बाँटा गया है। (1) स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना (2) स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना।

1 स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना :- इसकी शुरुआत 1 दिसम्बर 1997 को की गई। नेहरू रोजगार योजना, निर्धनों के लिए शहरी बुनियादी सेवाएं तथा प्रधान मंत्री सम्व समन्वित, शहरी गरीबी उन्मूलन योजना को इसी योजना के साथ समन्वित कर दिया गया है। इस योजना में केन्द्र सरकार की 75% और राज्य सरकार की 25% की भागीदारी होती है।

इस योजना के अन्तर्गत परियोजना लागत 30% या अधिकतम 7500रु. सब्सीडी के रूप में दिये जाते हैं। अनुसूचित जाति और अ. जनजाति के लिए यह सीमाएं 50% और 10,00 रू० होगी। स्वरोजगारियों के लिए समूह के लिए सब्सीडी परियोजना लागत का 50% और अधिकतम 1.25 लाख रू. की होगी। इस योजना के अन्तर्गत कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी गयी है। कुल सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों में 50% SC/ST, 40% तक महिलाओं और 3% विकलांगों के लिए आरक्षण की व्यस्था है।

इस संदर्भ में मुख्य समस्या यह है कि उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश गरीब राज्य निर्धारित धनराशि समय पर उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। इस योजना के अन्तर्गत चल रहे कार्यों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है।

(A) शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम

(B) शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में लागू किया गया। इस योजना का कार्य भी मुख्यतः शहरी स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना की तरह ही क्रियान्वित किया गया है, सिर्फ फर्क इतना है कि इस योजना को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्रियान्वित किया गया है।

उपरोक्त सभी तथ्यो के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भारत में गरीबी की दूर आज भी ज्यों का त्यों है। सरकार द्वारा योजनाओं पर पानी की तरह रू० को बहाया जा रहा है परन्तु इसका कोई सार्थक परिणाम सामने नहीं आ रहा है।

(6)

Page No.
Date

इसमें हम सब के साथ अधिकारी और राजनेता भी सम्मिलित जिसके कारण सार्थक परिणाम नहीं निकल पा रहा है। इसके लिए सरकार के द्वारा ठोस कदम उठाना चाहिए।

The End

Dr Pankaj Kumar yadav
S.N.S.R.K. college Saharsa
Department of L.S.W

Kyadav